

प्रेषक,

डी0एस0 गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

दिनांक:- 3/ जनवरी, 2013

विषय:-जनपद चमोली के अंतर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में सेना के उपयोग हेतु प्रस्तावित गैरीसैन इंजीनियर (एम0ई0एस0) पेयजल योजना हेतु कुल 0.310 है0 सिविल सोयम भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-277/छब्बीस-24(2011-12) दि0-8.10.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति के दृष्टिगत जनपद चमोली के अंतर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में सेना के उपयोग हेतु प्रस्तावित गैरीसैन इंजीनियर (एम0ई0एस0) पेयजल योजना हेतु ग्राम हेलंग के नॉन जेड0ए0 खसरा नं0-297 रकबा 1.093 मध्ये 0.170 है0 एवं ग्राम पैनी के नॉन जेड0ए0 खसरा सं0-1120 रकबा 1.935 है0 मध्ये 0.140 है0 कुल 0.310 है0 भूमि की कीमत प्रचलित बाजार की दर से वसूल किये जाने एवं भूमि के कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के सौ गुने के बराबर की धनराशि भारत सरकार के विभागों से पंजीकृत मूल्य के रूप में वसूल किये जाने के प्राविधान के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1.- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- 2.- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 3.- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85 (24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- 4- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 5- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- 6- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 7- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया तत्कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

पृ०प०सं०- १५४ /संमदिनांकित/2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पेयजल/सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।